संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट मूल रूप से सरकार के। अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, इसे सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामले विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है ।

अर्थव्यवस्था

- कैपेक्स का लक्ष्य (5.54 लाख करोड़ रुपये से 7.50 लाख करोड़ रुपये।) 35.4 प्रतिशत बढ़ा
- FY 23 प्रभावी कैपेक्स 10.7 लाख करोड़ रुपये पर देखा गया
- सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का विकास उच्चतम
- लक्ष्य सूक्ष्म समावेशी कल्याण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, तकनीक-सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई के साथ मैक्रो-विकास को पूरक बनाना है।
- इस वर्ष के बजट का मुख्य फोकस हैं: पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, निवेश का वित्तपोषण
- उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को 14 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है;(30 लाख करोड़ रुपये निवेश का इरादा)
- यह बजट सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय से लाभान्वित होने वाले आर्थिक सुधार। विकास को गति देगा

व्यय और घाटा

- 2025/26 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% प्रस्तावित राजकोषीय घाटा
- 2022/23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% का अनुमानित राजकोषीय घाटा
- 2021/22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% पर
- सामान्य उधारी के अलावा राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की अनुमति
- 2022/23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश परिव्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना

byjusexamprep.com

रुपया कहां से आता है Rupee Comes From

(बजट Budget 2022-23)

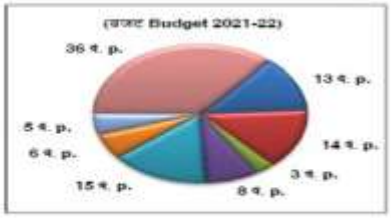

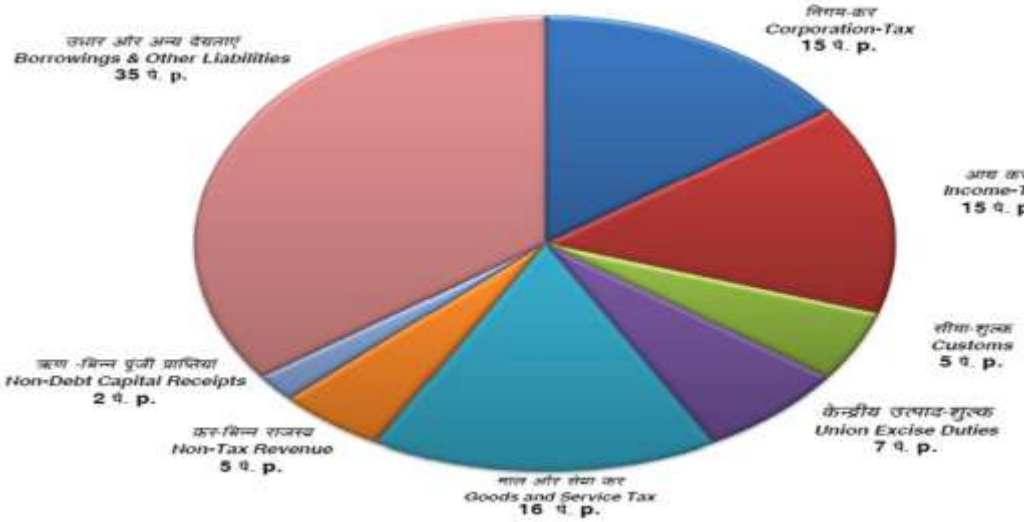

रुपया कहां जाता है Rupee Goes To

(बजट Budget 2022-23)

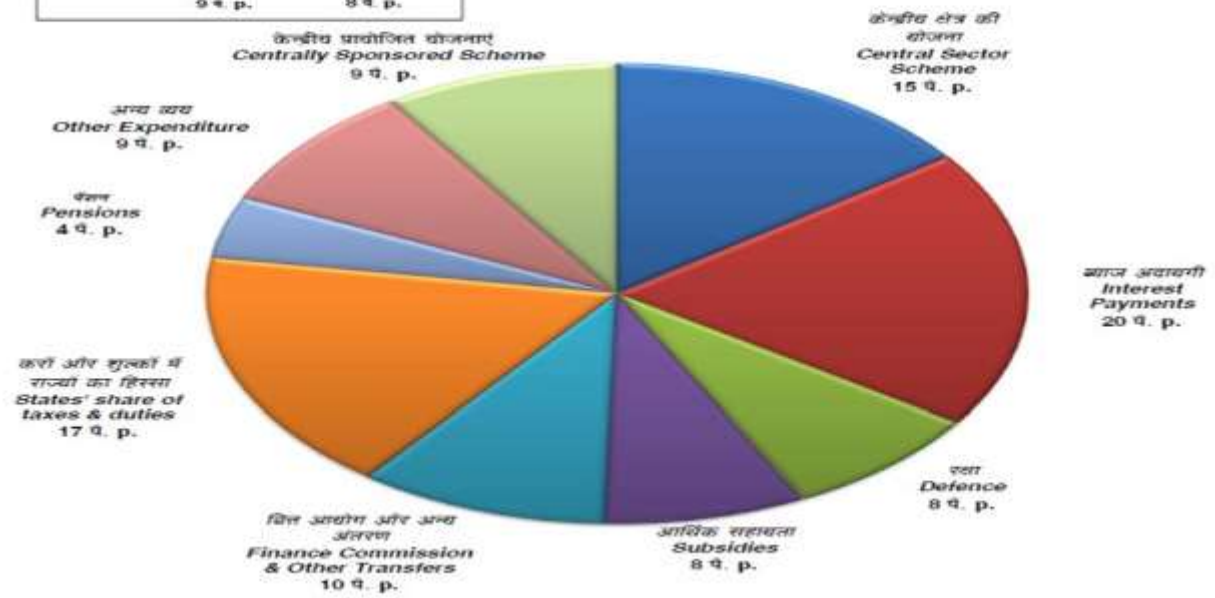

घाटे का सार Deficit Statistics

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2020-2021 वास्तविक Actuals	2021-2022 बजट अनुमान Budget Estimates	2021-2022 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2022-2023 बजट अनुमान Budget Estimates
1. राजकोषीय घाटा	1. Fiscal Deficit	1818291 (9.2)	1506812 (6.8)	1591089 (6.9)	1661196 (6.4)
2. राजस्व घाटा	2. Revenue Deficit	1449599 (7.3)	1140576 (5.1)	1088352 (4.7)	990241 (3.8)
3. प्रभावी राजस्व घाटा	3. Effective Revenue Deficit	1218734 (6.2)	921464 (4.1)	850667 (3.7)	672598 (2.6)
4. प्राथमिक घाटा	4. Primary Deficit	1138422 (5.8)	697111 (3.1)	777298 (3.3)	720545 (2.8)

घाटे की प्रवृत्तियां
DEFICIT TRENDS

(% of GDP)

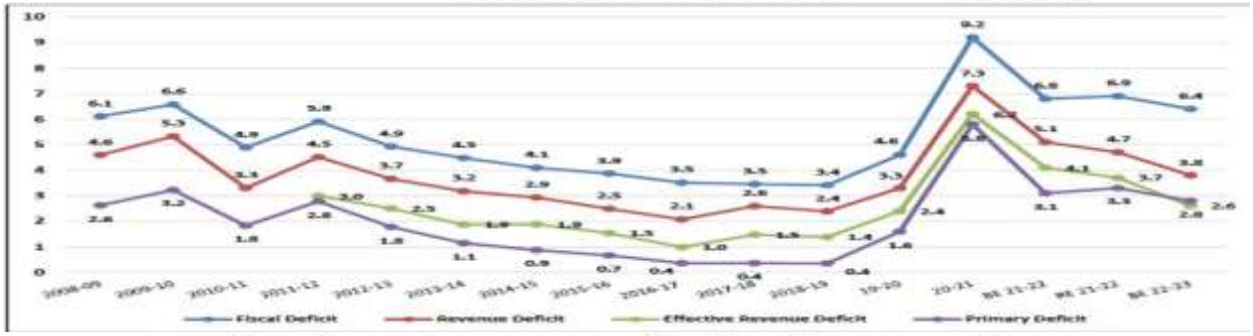

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण
TOTAL TRANSFERS TO STATES AND UTs

(₹ in lakh crore)

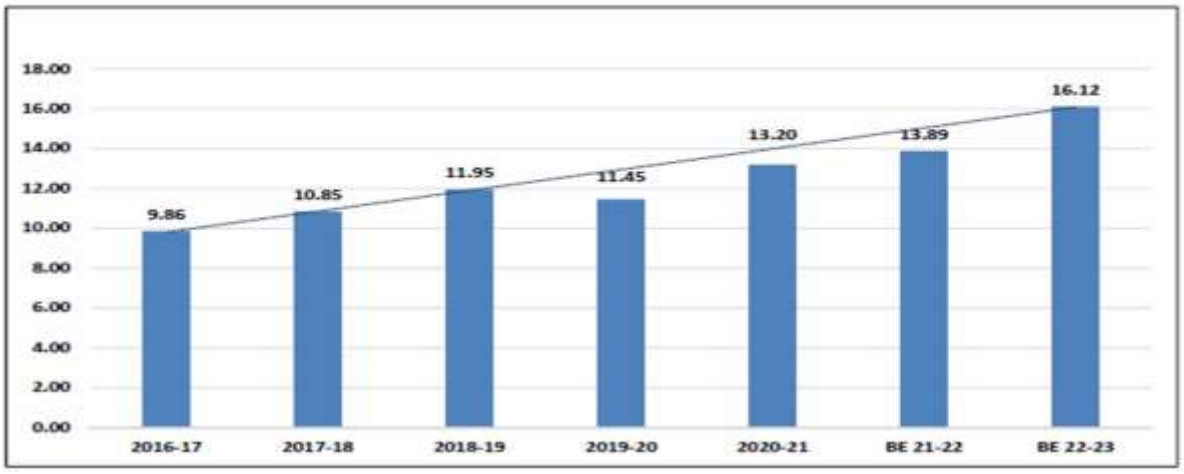

व्यय की संरचना

COMPOSITION OF EXPENDITURE

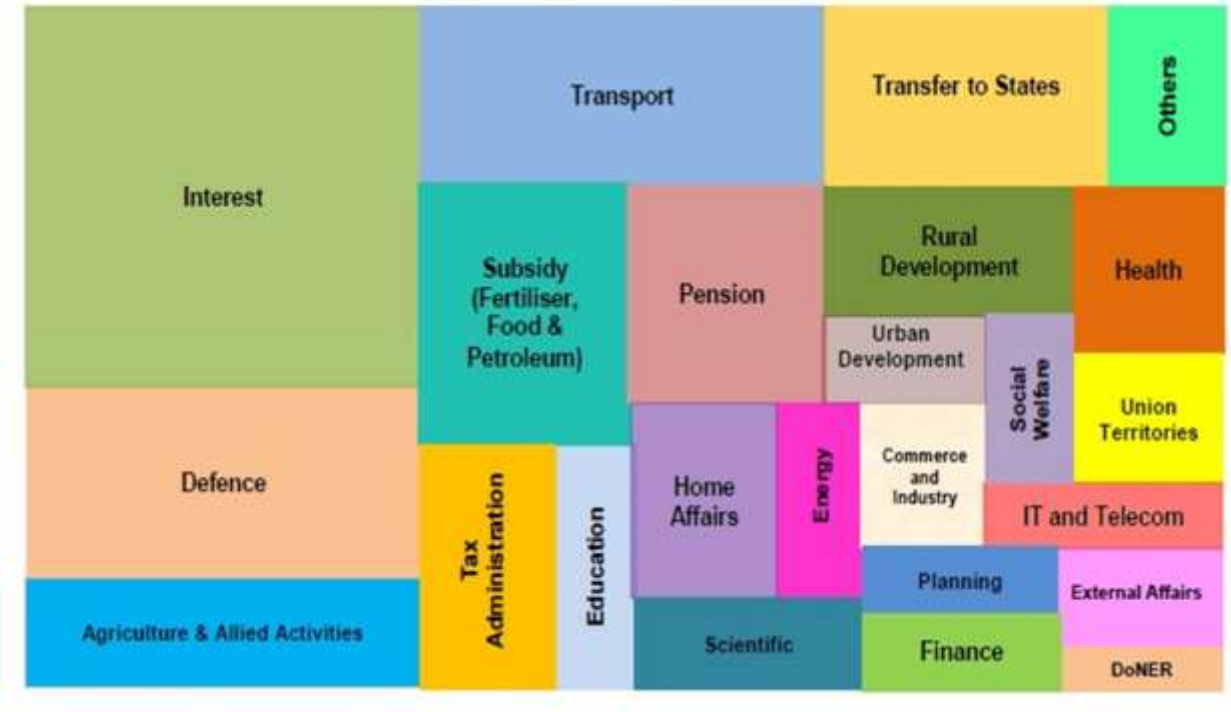

कर

- सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से आय पर 30% कर लगाएगी
- अधिग्रहण की लागत को छोड़कर आय की गणना करते समय किसी कटौती की अनुमति नहीं है
- क्रिप्टोकरंसीज के उपहार पर प्राप्तकर्ता की ओर से कर लगाया जाएगा
- प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर घटाकर 15% किया जाएगा
- सहकारी समितियों पर अधिभार को घटाकर 7% किया जाएगा जिनकी आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 14% की गई

नौकरियां

- ECLGS मार्च 2023 तक बढ़ा, अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियों पर नजरें
- केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमिता के अवसर
- स्किलिंग और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा।

byjusexam

- इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, कौशल, कौशल प्रदान करना है।
- API आधारित कौशल क्रेडेंशियल, प्रासंगिक नौकरियों और अवसरों को खोजने के लिए भुगतान परतें

आधारभूत संरचना और रेलवे

- वित्त वर्ष 22-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किमी तक विस्तारित किया जाएगा
- डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च होगा देश स्टैक ई-पोर्टल
- FY23 में चार मल्टी-मोडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे
- एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा
- अगले वित्तीय वर्ष में तैयार होगा एक्सप्रेस-वे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान
- 2,000 किमी रेल नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवर के तहत लाया जाएगा: FM

स्वास्थ्य सेवा

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा
- इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी
- 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है
- मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

महिला एवं बाल कल्याण

- नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए, महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की गईं
- बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों का उन्नयन

कृषि

- MSP संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी सरकार
- 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है

byjusexamprep.com

- फसल मूल्यांकन के लिए किसान ड्रोन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद
- केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा
- गंगा नदी गलियारे के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- पूरी तरह से पेपरलेस, खरीद के लिए मंत्रालयों द्वारा शुरू की जाने वाली ई-बिल प्रणाली

रक्षा

- सरकार आयात कम करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है
- रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 प्रतिशत स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास खोला जाएगा।
- निजी उद्योग को SPV मॉडल के माध्यम से DRDO और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों को डिजाइन और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा (पिछले वित्त वर्ष में 58% से अधिक)

ईज ऑफ डूइंग

- व्यवसायों के लिए इसे आसान बनाने के लिए 75,000 अनुपालन समाप्त किए गए और 1,486 संघ कानून निरस्त किए गए
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण शुरू होगा
- कॉरपोरेट्स के लिए स्वैच्छिक निकास 2 साल से घटाकर 6 महीने किया जाएगा
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की जगह नया कानून लाया जाएगा

शिक्षा

- प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, राज्यों को आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- PM eVIDYA के एक खंड, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा
- इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे
- शिक्षा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हब और स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा
- कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1-कक्षा-1-टीवी चैनल लागू किया जाएगा

byjusexamprep.com